कांग्रेस आंदोलन की बजाए किसानों से माफी मांगे

हेमंत खण्डेलवाल ने कांग्रेस के आंदोलन की घोषणा पर कहा-

12 साल में समर्थन मूल्य 1600 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा

नवभारत समाचार

भोपाल, 6 मई. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने प्रदेश कांग्रेस द्वारा गुरुवार को प्रस्तावित किसान चक्काजाम आंदोलन को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह चक्काजाम निजी राजनीतिक स्वार्थ का चक्काजाम है. यह आमजन को बंधक बनाने जैसा कृत्य है, जिससे एंबुलेंस और अग्निशमन जैसी आपात सेवाएं प्रभावित होंगी.

खंडेलवान ने एक बयान के जरिए कहा कि प्रदेश के किसानों के नाम पर किया जा रहा यह आंदोलन गैर-जिम्मेदाराना और जनविरोधी है, जो प्रदेश की जनता, व्यापार और व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाला है. कांग्रेस व जीतू पटवारी को किसानों के मुद्दे पर आंदोलन नहीं, बल्कि छल व झूठ के लिए माफी मांगना चाहिए.

कांग्रेस को किसानों के मुद्दों पर आंदोलन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार किसानों से एक-एक दाना गेहूं खरीदने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है.

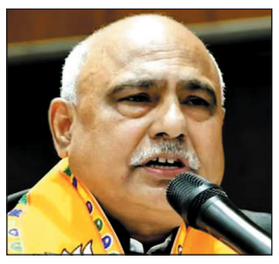

कांग्रेस ने कर्जमाफी के झूठे वादों से किसानों को डिफाल्टर बना दिया था, भाजपा सरकार ने किसानों की लगभग 2800 करोड़ की राशि जमा कर उन्हें डिफाल्टर की श्रेणी से बाहर निकाला. कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वर्ष 2003-04 में गेहूं का समर्थन मूल्य क्या था और क्या उस समय किसानों का अनाज समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता था.

प्रदेश अध्यक्ष खण्डेलवाल ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए गठित स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को भी कांग्रेस सरकारों ने वर्षों तक लागू नहीं किया. वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों को लाभकारी समर्थन मूल्य मिलने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए. कांग्रेस के 55 साल के कार्यकाल में गेहूं का समर्थन मूल्य सिर्फ पांच सौ रूपए तय था. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 12 साल में गेहूं का समर्थन मूल्य लगभग 1600 रूपए प्रति क्विंटल बढ़ाया जा चुका है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार किसानों को एमएसपी पर बोनस देकर 2625 रुपये प्रति क्विंटल के मान से गेहूं खरीदी कर रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों से एक-एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है. कांग्रेस शासनकाल में जहां गेहूं का उत्पादन लगभग 60 लाख टन था, वहीं आज यह बढ़कर करीब 200 लाख टन तक पहुंच गया है. किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं भाजपा सरकार की देन हैं. उन्होंने कहा कि गेहूं उपार्जन में प्रारंभिक देरी बारदानों की कमी के कारण हुई थी, लेकिन अब खरीदी तेज गति से जारी है और इसके प्रभाव से बाजार में गेहूं के दाम भी 100 से 200 रुपये तक बढ़े हैं.

आंदोलन करने से पहले आत्मचिंतन करे कांग्रेस

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि कांग्रेस किसानों को भ्रमित कर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है. जीतू पटवारी को पहले किसानों से माफी मांगनी चाहिए और यह बताना चाहिए कि कांग्रेस सरकारों, विशेषकर 15 माह की कमलनाथ सरकार ने किसानों के लिए क्या ठोस कार्य किए .भाजपा सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा. सरकार किसानों की आय बढ़ाने, लागत कम करने, उचित मूल्य दिलाने और कृषि जोखिमों को कम करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. मध्यप्रदेश आज दलहन उत्पादन में देश में प्रथम तथा खाद्यान्न व तिलहन उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, जो सरकार की किसान हितैषी नीतियों का परिणाम है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस आंदोलन करने से पहले आत्मचिंतन करे और किसानों से माफी मांगे.

वित्त सेवा अधिकारी संघ के चुनाव की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी

उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने किया संघ की वेबसाइट को लांच

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 6 मई. उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को मंत्रालय में मप्र. वित्त सेवा अधिकारी संघ की वेबसाइट लांच की. उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने वेबसाइट को राज्य के वित्त सेवा अधिकारियों एवं अन्य विभागों के अधिकारियों के लिए अत्यंत उपयोगी बताया. इस दौरान उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी. उन्होंने इस पहल को नवाचार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.

वित्त सेवा अधिकारी संघ के अध्यक्ष रणजीत सिंह चौहान ने जानकारी दी कि देश में पहली बार किसी अधिकारी/कर्मचारी संघ द्वारा चुनाव की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है. इस व्यवस्था मे प्रदेश में कहीं भी पदस्थ वित्त सेवा अधिकारी अपने संघ के चुनाव के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, नाम वापस ले सकेंगे तथा ऑनलाइन मतपत्र के माध्यम से मतदान भी कर सकेंगे. इस प्रकार संघ के पदाधिकारियों का चुनाव पूर्णत: ऑनलाइन संपन्न होगा. उन्होंने बताया कि वेबसाइट पर एक क्लिक में महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.

सवारी डिब्बा कारखाना भोपाल ने 96 कोचों का अनुरक्षण किया

भोपाल, 6 मई. पश्चिम मध्य रेल के भोपाल रेल कारखाने में कोचों का पीरियोडिक ओवरहॉलिंग कार्य निरंतर उत्कृष्टता के साथ किया जा रहा है. मुख्य कारखाना प्रबंधक के मार्गदर्शन में अनुरक्षण डिपो ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम माह अप्रैल में 96 कोचों का सफलतापूर्वक पीरियोडिक ओवर हॉलिंग (पीओएच) कर बेहतरीन प्रदर्शन किया है.

बता दें कि पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में पश्चिम मध्य रेल के सवारी डिब्बा पुर्ननिर्माण कारखाना भोपाल ने 1336 कोचों का अनुरक्षण किया गया. वरिष्ठ अधिकारियों की सतत निगरानी में भोपाल कारखाना प्रबंधन ने टीम भावना और सुनियोजित कार्ययोजना के साथ यह सफलता हासिल की. पीरियोडिक ओवर हॉलिंग के दौरान निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं: कोचों की बॉडी और अंडरगियर की मरम्मत कर परिचालन में अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है. ट्रॉली, बोगी के सभी महत्वपूर्ण पार्ट्स की मरम्मत की जाती है, जो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. व्हील और एक्सल का रखरखाव और मरम्मत कर परिचालन सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाता है.

भोपाल मंडल में यात्री सुविधाओं का विस्तार

डीआरएम पंकज त्यागी की अगुवाई में यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है. इस उद्देश्य से पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल द्वारा विभिन्न स्टेशनों पर आधारभूत संरचना एवं यात्री सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है. भोपाल मंडल के 85 स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा उपलब्ध है, जिससे यात्रियों को बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी मिल रही है. सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया की इन सभी प्रयासों के माध्यम से यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी, सुगम आवागमन, समय की बचत एवं आधुनिक टिकटिंग विकल्प प्राप्त हो रहे हैं. भोपाल मंडल भविष्य में भी यात्रियों की सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए निरंतर विकास कार्य करता रहेगा.

आंगनबाड़ी केंद्रों में अनियमितता पर नोटिस जारी

सिंगरौली. शहरी परियोजना अधिकारी द्वारा आज पंजरेह झिंगुरदह बस्ती क्षेत्र के तीन आंगनबाड़ी केंद्रों, कांटा बैरियर झिंगुरदह, चन्द्रपुर एवं खैरवाही बस्ती झिंगुरदह का निरीक्षण किया गया. तीनों केंद्र संचालित पाए गए, जहाँ बच्चों की लंबाई एवं वजन का भौतिक सत्यापन सीधे पोषण ट्रैकर एप के माध्यम से किया गया. वहीं स्व-सहायता समूहों द्वारा भोजन तो मीनू के अनुसार वितरित किया जा रहा था, किंतु नाश्ता वितरण में निर्धारित मीनू का पालन नहीं करने पर संबंधितों को नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जा रही है. टीकाकरण की भी समीक्षा इस दौरान की गई.

किसानों के मुद्दों पर कांग्रेस का प्रदेशव्यापी आंदोलन आज

समर्थन मूल्य में अंतर और खरीद अव्यवस्था को लेकर सरकार घिरी

विशेष संवाददाता

भोपाल, 6 मई. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों के साथ कथित अन्याय, शोषण और सरकारी उदासीनता के विरोध में 7 मई को प्रदेशव्यापी चक्का जाम आंदोलन की घोषणा की है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस 'सड़क से लेकर जेल तक' आंदोलन तेज करेगी.

पटवारी ने सरकार पर किसानों से किए वादों से मुकरने का आरोप

लगाते हुए कहा कि समर्थन मूल्य और वास्तविक खरीदी दर के बीच अंतर के कारण किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. जहां सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया था, वहीं खरीदी 2625 रुपये प्रति क्विंटल पर की जा रही है, जो किसानों के साथ सीधा अन्याय है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुल उत्पादन की तुलना में खरीदी की मात्रा सीमित है, जिससे बड़ी मात्रा में गेहूं बिना बिके रह जाता है और किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता. पटवारी ने धान खरीदी, उर्वरक और कृषि उपकरणों से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार की विफलता का आरोप लगाया. कांग्रेस और किसान संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में 7 मई को सुबह 11 बजे से मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-3) सहित विभिन्न स्थानों पर चक्का जाम किया जाएगा. यह आंदोलन प्रदेश के कई जिलों में व्यापक स्तर पर आयोजित होगा. मुरैना (मुरैना, भिंड), ग्वालियर (ग्वालियर, दतिया), शिवपुरी (शिवपुरी, श्योपुर), गुना (गुना, अशोकनगर), शाजापुर (शाजापुर, देवास, राजगढ़, आगर मालवा, उज्जैन, सीहोर, विदिशा, रायसेन, भोपाल), इंदौर और खलघाट (धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ) में भी यह चक्काजाम व्यापक स्तर पर करने की घोषणा

गेहूं खरीदी व्यवस्था 'ध्वस्त', कांग्रेस का आरोप

प्रदेश में गेहूं खरीदी व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की खरीदी प्रणाली लगभग 'ध्वस्त' हो चुकी है और यह किसान विरोधी होने के साथ प्रशासनिक विफलता का उदाहरण बन गई है. कांग्रेस का कहना है कि खरीदी और स्लॉट बुकिंग की तिथियों को बार-बार बढ़ाया जाना खराब प्रबंधन और तंत्र की कमजोरियों को उजागर करता है .भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता को पी .सी. शर्मा, प्रवीण सक्सेना, अनोखी मानसिंह पटेल, अरुण श्रीवास्तव, अभिषेक शर्मा और जितेंद्र मिश्रा ने संबोधित किया.

कई जिलों में आंधी और बारिश का दौर शुरू

भोपाल, 6 मई. मध्यप्रदेश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है. बुधवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बनी रही. जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली.

वहीं मौसम विभाग के अनुसार बालाघाट और दक्षिण सिवनी में मध्यम स्तर की गरज चमक भी देखने को मिली. इस वही कई जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चली. इसके साथ ही पांढुर्णा, दक्षिण पूर्व बैतूल और दक्षिण मंडला या कान्हा क्षेत्र में हल्की गरज चमक की संभावना बनी रही. मौसम वैज्ञानिकों ने आगामी दिनों के लिए प्रदेश के विभिन्न

भोपाल के मौसम का हाल

राजधानी भोपाल में भी मौसम के मिजाज में बदलाव देखा जा रहा है. भोपाल में बादलों की मौजूदगी के कारण तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है. वहीं बुधवार को भोपाल का अधिकतम 38 .2 तथा न्यूनतम 22डिग्री तापमान रहा. जहां गर्मी का असर काफी तेज रहा. वहीं प्रदेश का सबसे कम तापमान पचमढ़ी में रहा जहां मौसम सुहावना बना हुआ है. भोपाल के तापमान की बात करें तो आज अधिकतम तापमान 40 .5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 .2 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया.

जिलों में आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी जारी की है. आने वाले समय में अनूपपुर, शहडोल, उमरिया और डिंडोरी जैसे पूर्वी जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है. वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान में सक्रिय मौसमी सिस्टम के कारण दक्षिण और पूर्वी मध्यप्रदेश के जिलों में मौसम का असर अधिक रहेगा.

प्रशासन ने नागरिकों को बिजली चमकने के दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है. किसानों को भी अपनी कटी हुई फसल सुरक्षित स्थानों पर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि अचानक होने वाली बारिश से नुकसान न हो.

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के कुलगुरु ने किया निरीक्षण

भोपाल 6 मई. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर एस के जैन ने विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं के अंतर्गत रायसेन जिले के शासकीय महाविद्यालय बरेली सहित बरेली और सिलवानी के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का बुधवार को औचक निरीक्षण किया.

यह निरीक्षण परीक्षाओं के सुचारु और सफल संचालन को लेकर किया गया. कुलगुरु ने सबसे पहले शासकीय महाविद्यालय बरेली पहुंचकर परीक्षा कक्ष कंट्रोल रूम और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने केंद्र अध्यक्ष से विषयवार और कक्षवार छात्रों की जानकारी मांगी.

साथ ही प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं के स्टॉक रजिस्टर वीक्षकों की संख्या और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली. निरीक्षण के दौरान केंद्र अध्यक्ष और महाविद्यालय के प्राचार्य के अनुपस्थित पाए जाने पर कुलगुरु ने नाराजगी व्यक्त की.

मंत्री राजपूत ने किया उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण

भरे बोरे के गेहूं का वजन कराया

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 6 मई. प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बुधवार को भोपाल से सागर जाते समय अचानक रायसेन जिले के सेहतगंज स्थित उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया.

मंत्री राजपूत ने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए तुलाई, खरीदी एवं अन्य व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी प्राप्त की. उन्होंने मौके पर बारदाने का वजन कराया और भरे बोरे के गेहूं का वजन कराया.

निरीक्षण के दौरान मंत्री राजपूत ने उपार्जन केंद्र पर व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की तथा ऑटो कनेक्टिविटी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने खरीदी के दौरान पारदर्शिता बनाए रखने और तुलाई प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता न होने के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए. मौके पर कार्य में थोड़ी शिथिलता पाए जाने पर खाद्य मंत्री राजपूत ने संबंधित सर्वे कर्मचारियों वसुंधरा गौर और शिवराज लोधी को कड़ी फटकार लगाते हुए कार्य में सुधार लाने के निर्देश दिए.

जाटव ने अजा आयोग में पदभार ग्रहण किया

दोनों सदस्यों ने भी संभाला दायित्व

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 6 मई. मप्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ. कैलाश जाटव तथा सदस्य रामलाल मालवीय एवं बारेलाल अहिरवार ने बुधवार को आयोग में पदभार ग्रहण किया.

इस अवसर पर आयोजित समारोह में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. गौतम टेटवाल, राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी, सांसद महेंद्र सोलंकी, राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया, विधायक भगवानदास सबनानी, विधायक विष्णु खत्री एवं निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे.

अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे चयनित शिक्षक

भोपाल, 06 मई. प्रदेश में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर चयनित अभ्यर्थियों के सब्र का बांध अब टूट गया है. राजधानी भोपाल स्थित लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई में अपनी नियुक्ति की गुहार लेकर प्रदेश भर से आए करीब 300 से अधिक अभ्यर्थी बुधवार को दोपहर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं.

जबलपुर दमोह और इंदौर सहित कई अन्य जिलों से आए इन युवाओं का कहना है कि सरकार पिछले आठ महीनों से उन्हें केवल कोरा आश्वासन दे रही है और अब वे बिना लिखित आदेश के यहाँ से नहीं हटेंगे. जबकि बुधवार भी डीपीआई में मांगो का ज्ञापन देने के बाद अभ्यर्थियों को कोई लिखित आश्वाशन नहीं प्राप्त हुआ है.

नियम पुस्तिका का उल्लंघन और पंचवर्षीय योजना बनी भर्ती: अभ्यर्थियों के अनुसार परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका के अनुसार रिक्त पदों पर चयन सूची जारी होने के तीन माह के भीतर नियुक्ति आदेश जारी होना अनिवार्य है. भर्ती प्रक्रिया की सुस्त रफ्तार पर सवाल उठाते हुए अभ्यर्थियों ने कहा कि जिस प्रक्रिया को 2024 तक पूरा हो जाना चाहिए था. उसे अब 2026 तक खींचकर पंचवर्षीय योजना बना दिया गया है. सितंबर 2025 में परिणाम आने के बावजूद अब तक न तो पात्र अपात्र की सूची जारी हुई है और न ही चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है.

दो दो परीक्षाएं पास फिर भी सड़क पर रहने को मजबूर: प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उन्होंने माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक वर्ग दो और तीन के लिए पात्रता और चयन जैसी दो कठिन परीक्षाएं पास की हैं. इसके बावजूद 10700 चयनित अभ्यर्थी आज सड़क पर आने को मजबूर हैं. विभाग बार बार कोर्ट केस का हवाला देता है. जबकि इस भर्ती पर किसी भी प्रकार का कोई स्टे नहीं है.

अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगें

- चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र अति शीघ्र नियुक्ति आदेश जारी किए जाएं.
- पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची तत्काल प्रभाव से पोर्टल पर अपलोड की जाए.
- चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर जॉइनिंग की समय सीमा तय हो.
- रिक्त पदों को तत्काल भरकर प्रदेश की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार किया जाए.

सिंहस्थ-2028 की तैयारियां | **अभूतपूर्व भीड़ की संभावना देखते हुए बैठक में समग्र योजना पर विस्तार से की गई चर्चा**

उच्च स्तरीय समन्वय बैठक में बनी व्यापक रणनीति

विशेष संवाददाता

भोपाल, 6 मई. सिंहस्थ-2028 के सुव्यवस्थित और सुरक्षित आयोजन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी क्रम में भोपाल में पुलिस, रेलवे, जीआरपी, आरपीएफ और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित कर विशाल धार्मिक आयोजन के लिए व्यापक रणनीति तैयार की गई. बैठक में अभूतपूर्व भीड़ को ध्यान में रखते हुए समग्र योजना पर विस्तार से चर्चा की गई.

बैठक में प्रयागराज महाकुंभ-2025 के अनुभवों से सीख लेते हुए आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया. पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने कहा कि श्रद्धालुओं की संख्या पूर्व आयोजनों से अधिक रहने की संभावना है, इसलिए सभी विभागों के बीच मजबूत तालमेल अत्यंत आवश्यक है. उज्जैन, इंदौर, रतलाम, भोपाल, ओंकारेश्वर रोड और सीहोर के रेलवे स्टेशनों पर आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया गया. फुटओवर ब्रिज चौड़े करने, संकेतक सुधारने, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम मजबूत करने और अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन जैसे उपायों पर सहमति बनी. बहु-स्तरीय क्राउड मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से रियल-टाइम मॉनिटरिंग और एआई आधारित निगरानी प्रणाली लागू करने पर भी चर्चा हुई. साथ ही खुफिया तंत्र मजबूत करने को प्राथमिकता दी गई.

रेलवे अधिकारियों ने 2016 की तुलना में तीन गुना अधिक विशेष ट्रेनें चलाने, डायनेमिक टाइम टेबल और शॉर्ट डिस्टेंस शटल सेवाएं संचालित करने की योजना साझा की. 9 अप्रैल से 8 मई 2028 तक चलने वाले इस आयोजन में करीब 30 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जबकि शाही स्नान के दिनों में एक दिन में 5 करोड़ तक श्रद्धालु पहुंच सकते हैं. बैठक में एडीजी ए. साईं मनोहर, राजाबाबू सिंह, राकेश गुप्ता, उज्जैन कमिश्नर आशीष सिंह, कलेक्टर रोशन सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा, डीआईजी नवनीत भसीन और तरुण नायक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

कैग की रिपोर्ट ने खोली शिक्षा व्यवस्था की पोल

चयनित शिक्षकों ने मध्यप्रदेश विधानसभा में पेश हुई कैग की ताजा रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश के 1895 स्कूल ऐसे हैं जहां छात्र तो हैं लेकिन एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है. प्रदेश भर के स्कूलों में 99682 शिक्षकों की भारी कमी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है. अभ्यर्थियों का तर्क है कि जब पद खाली हैं और योग्य शिक्षक चयनित होकर तैयार हैं तो फिर जॉइनिंग में देरी क्यों की जा रही है.